



Neutral Citation-2026: AHC:20607

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 3009 / 2026

शोभनाथयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अम्पाली सिंह, एकांश वर्मा

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. खसरा संख्या 505M पर स्थित 0.0180 हेक्टेयर ज़मीन का एक टुकड़ा, जो तेहदुअकलां, तहसील लालगंज, ज़िला मिर्ज़ापुर में स्थित है, 25.02.2019 को याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था। जब प्रतिवादी संख्या 5/गंगाई ने विवादित ज़मीन पर अतिक्रमण करना शुरू किया, तो याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें 28.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील लालगंज, ज़िला मिर्ज़ापुर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 5 को संबंधित ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उक्त आदेश अंतिम हो चुका है, फिर भी आज तक उसका पालन नहीं किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तथापि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर इस मामले में अत्यंत शीघ्रता से, और अधिमानतः उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर, निर्णय लेंगे।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"